]Shri K. R. Ganesh]

our credit institutions and the banks we have taken credit to the poorest and the vulnerable and disadvantaged sections of the society. The new decision for conversion of loans into equity and the enforcement of the monopoly laws are steps in this direction.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has to conclude now because we have to take up the Private Members' Business.

SHRI K. R. GANESH : I shall try to finish as early as possible.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can take one minute now and, if necessary, continue tomorrow.

SHRI K. R. GANESH : These are some of the concrete measures that this government has taken. I would ask Shri Indrajit Gupta, for whom I have great respect, that within the framework of the parliamentary democracy, what are the concrete steps that the Communist Party of India want us to take ? He has said : nationalise the 75 monopoly houses.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Will you give me another chance to speak ?

SHRI K. R. GANESH : He says : nationalise the 75 monopoly houses and nationalise foreign investment. As far as nationalisation is concerned, wherever this government has found it necessary in the interest of the national economy, it has not failed to do that, as will be borne out by the history of this government for the last 24 years. In the context of parliamentary democracy, in the context of our Constitution, particularly article 246, in the context of our existing laws, what are the concrete steps which he would advocate ? This is my very sincere poser to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may continue his speech tomorrow. We will now take up Private Members, business.

15.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

TENTH REPORT

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move :

> "That this House do agree with the Tenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd March, 1972 "

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That this House do agree with the Tenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd March, 1972 "

The motion was adopted.

RESOLUTION RE: UNEMPLOYMENT PROBLEM—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further discussion of the Resolution on Unemployment moved by Shri Bibhuti Mishra on 10th December, 1971. Out of 1 hour 30 minutes allotted for this resolution we have taken 53 minutes and 37 minutes remain. Shri M. C. Daga has to continue his speech.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय वयोवृद्ध अनुभवी श्री विभूति मिश्र जी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। एक बात उन्होंने बतलाई थी कि बेकारों की जो बाढ़ आने वाली है उससे पहले ही हमको कोई कदम उठाने चाहिएं। एक बात यह भी है कि हमारी सरकार के केवल आदर्शवादी, लुभावने और थोथे नारों से नाराज और

असन्तुष्ट युवक प्रसन्न नही हो सकते। जब तक हमारे कदम बेकारी को दूर करने के लिए मजबूती के साथ नही उठाये जायेंगे तब तक मै समझता हूँ आने वाले समय मे बेकारी की जो सख्या बढती जा रही है उसमे स्थिति और खराब होती जायेगी। इसलिए हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम बेकारी के मामले मे तेजी के साथ मजबूती से कदम उठाये।

(व्यवधान) इसलिए मै समझता हूँ कि जो सकल्प माननीय विभूति जी ने रखा है वह बहुत ही सही और आवश्यक है। इस समय इस देश मे यदि कोई सबसे बडा अभिशाप है तो वह बेकारी है। आज जब मै बेकार युवको के हीन भावना से ग्रसित चेहरो को देखता हूँ तो उन पर हिम्मत की कोई रेखाये नजर नही आती। उनको आज अपनी जिन्दगी का कोई भविष्य नजर आ रहा है। वे इस मामले मे सरकार को कोसते है और समझते है कि इस समाज मे पैदा होकर और अपने मजबूत हाथो को लेकर भी उनको काम नही मिलता। इस प्रकार जो मशक्त हाथ बेकार रहते है उनको काम देने की जिम्मेदारी सरकार को होती है। आज देश के सामने एक बडा भारी सवाल पैदा हो गया है कि अगर बेकारो की बाढ को नही रोका गया, उनकी बेकारी को दूर करने के लिए मजबूत कदम नही उठाए गए तो लोगो मे विप्लव, अशाति और हलचल पैदा होगी और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर आयेगी। योजनाओ मे बेकारी की समस्या का निराकरण नही होगा उससे मुश्किल आने का खतरा है। मै इस बात के लिए आपकी सेवा मे पढकर बताना चाहता हूँ कि इसमे कितना नुकसान होता है

MR DEPUTY-SPEAKER You had taken seven minutes on the previous occasion

SHRI M C DAGA I will take ten minutes and finish my speech

MR DEPUTY SPEAKER Out of 1 hour 30 minutes, you want ten minutes more? You are perhaps repeating the same arguments that you used in the last speech

SHRI M C DAGA No Sir I will not repeat those points I am not in the habit of repeating I will tell you certain new things

MR DEPUTY SPEAKER How do you know? It was months ago Please conclude now

SHRI M C DAGA Sooner the youthful spirit is channelized into useful purposes and new horizon of creative national activities shown to them better it would be for the economic regeneration of the country Failing this economic chaos with far reaching social consequences is inevitable

तो बेकारी की जो समस्या बढ रही है जिसके लिये मैने पहले भी सारे आकडे दिए थे और आज भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश मे कम से कम 10 करोड लोग ऐसे है जिनको 25 पैसे प्रतिदिन से कम मिलता है। नेशनल सेम्पल रिपोर्ट के अनुसार एक प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन की औसत आय केवल 92 पैसे है। इसको दूर करने का केवल एक ही साधन है और वह है ग्राम कुटीर उद्योग। हम गाँवो मे छोटे छोटे उद्योग शुरू करदे छोटे छोटे उद्योगो को चालू करे। इसके अतिरिक्त जैसा कि गाँधी जी ने खादी की बाबत बतलाया था उसके सम्बन्ध मे भी हम कदम उठाये। इन कदमो को उठाकर मै समझता हूँ हम बहुत जल्दी इस समस्या को हल कर सकते है। मै योजना पुस्तिका से उद्धृत कर रहा हूँ इन आकडो के तुलनात्मक अध्ययन से प्रकट है कि भारत जैसे निर्धन और श्रमसघन देश के लिए खादी कार्यक्रम ही सर्वाधिक लाभप्रद और व्यावहारिक है। इतना ही नही कपडा कारखाने मे मजदूर की वार्षिक आय प्रति मजदूर पूजी निवेश का केवल 0.2 प्रतिशत है जबकि चरखा परियोजना मे श्रमिक की सालाना आय पूजी निवेश का 85 प्रतिशत

[श्री मूल चन्द डागा]

है। क्या अब भी खादी को अनार्थिक कहना उचित है ? खादी अर्थ-व्यवस्था में पूंजी का केन्द्रीकरण संभव नही होता। कारण यह कि खादी द्वारा 85 प्रतिशत पूंजी भूखे और गरीब लोगो के पास पहुँचती है, लेकिन औद्योगीकरण मे 75 प्रतिशत से अधिक पूंजी कुछ पूंजीपतियो के पास केन्द्रित हो जाती है। इसलिए गाँधी जी ने खादी कार्य को "कताई यज्ञ" की पावन संज्ञा देते हुए कहा कि खादी, विकेन्द्रीकरण की अर्थनीति का मूर्तिमान रूप है।"

उन्होंने बतलाया था कि कम से कम हम एक रुपया 25 पैसा फी आदमी को दे सकते है। तो जो छोटे-छोटे ग्राम उद्योग है उनकी तरफ पूरा पूरा ध्यान दिया जाये। सरकार की जो प्लानिंग है उसके सम्बन्ध मे मैंने कहा था कि जो डिग्रियाँ देते है ला-ग्रैजुएट्स को उसके लिये भी कोई प्लान नही है। जितने अरब के देश है वे अगर किसी को डिग्री देते है तो साथ मे सर्विस भी देते है।

MR. DEPUTY-SPEAKER . Please try to conclude now.

SHRI M. C. DAGA : I am concluding in a minute. I want to read a relevant quotation from here .

> "The Education Commission suggested that under a good arrangement every graduate should be given along with his degree or diploma, an offer of appointment as well. This offer need not be binding...But a compulsion on the State to make such an offer would be the surest guarantee that the output of the educational system is closely linked with employment opportunities or manpower needs...All the evidence from countries that have adopted guaranteed employment for university graduates, such as, the United Arab Republic..."

This is done in so many countries. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से देश में जो बेकार आदमी पैदा हो रहे हैं उनके अन्दर हीन भावना पैदा होती है जिससे इस देश के राष्ट्रीय जीवन में गिरावट आती है, देश का स्तर उससे नीचे गिरता है और ऐसी स्थिति में हम इस देश को आगे नहीं बढा सकते।

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Minister.

SOME HON. MEMBERS *Rose*—

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : My party has not got an opportunity to speak on this Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Kindly listen to me also. 1 hour and 30 minutes are allotted to this Resolution We have already taken 53 minutes Only 37 minutes remain. Out of this, the Minister has to inevrenc and the mover of the Resolution has to reply. Moreover, this question of unemployment has also found a large part in the debate on the Budget. There is another very important Resolution also coming up.

SHRI S. M. BANERJEE : The Resolution moved by Shri Bibhuti Mishra is an important one. The usual practice in this House has been to extend the time on such important Resolutions. The political parties would like to take part in it and have some say in the matter. I would request you to extend the time. I move that the time be extended by 45 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is upto the House. If you want to extend the time on this Resolution, I can accommodate a few more Members. By how much time do you want to extend ?

SHRI NAVAL KISHORE SHARMA (Dausa) : 30 minutes.

AN HON. MEMBER : One hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us be realistic.

SHRI S. M. BANERJFE : Make it 45 minutes.

MR. DEPUTY-SPFAKER All right Shri S M. Banerjee

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका मिला कि मैं भी अपने दल के विचार इस सबध मे रख सकूँ। मै माननीय विभूति मिश्र जी को बधाई देता हूँ कि उन्होने सदन मे इस प्रस्ताव को पेश किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बेकारी और भुखमरी की दौड हिन्दुस्तान मे हो रही है, और मै जानता हूँ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो घोषणा की गयी थी इस देश म तो कहा गया था कि 8 मिलियन नये जौब्स क्रीएट किये जायेंगे, और मै जानता हूँ कि उस घोषणा को सुनकर कितनी खुशी की लहर दौड गयी थी लोगो मे जो एमप्लायमेट ऐक्सचेजेज के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो रहे थे। लेकिन तीन महीने के बाद ही देखाकि तकरीबन बेकारी की तादाद 88 लाख से बढकर एक करोड 25 लाख हो गयी। समझ म नही आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया जब कि 80 लाख लोगो को नौकरी मिलने जा रही थी तो बेकारो की तादाद 88 लाख से बढकर 1 करोड 25 लाख कैसे हो गयी ? ख्याल आया कि कही होम्योपैथी की दवाई तो नही है जो पहले बीमारी को बढाकर फिर उसको घटाया जाये। मालूम हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना मे बेकारी ज्यादा बढी। तीसरी पंचवर्षीय योजना मे हमने सोचा था कि शायद बेकारी कुछ कम होगी। लेकिन वह भी कम नही हुई। और आज उपाध्यक्ष महोदय, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ और खासकर सत्तारूढ दल, जिसको बहुमत प्राप्त है इस सदन मे और भारत की तमाम असेम्बलियों मे, वह भी इस बात को सोच जरूर रही है कि बेकारी को किस तरह से दूर किया जाये।

गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और गरीबी हटाने के साथ-साथ उन लोगो को भी हटा दिया गया जो उस रास्ते मे बाधक बनने जा रहे थे, यानी राजा, महाराजा। लेकिन सरमायेदार आज भी नही हटे। किसी न किसी रूप मे आज भी वे मौजूद है। अभी जवाब देते हुए माननीय के० आर० गणेश ने कहा कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी के पास कौन सी ऐसी चीज है, क्या प्लानिंग है कि जिससे तमाम चीजे हल हो सकती है ? मै केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि एकाधिकार को आप खत्म करे। मोनोपली हाउसेज, एकाधिकार समाप्त करने की जब बात कहता हूँ तो वह डौगमा के लिहाज से नही कहता। लेकिन क्या यह बात सही नही है कि वाकई मे आज भारत मे 75 परिवारो के हाथो मे हिन्दुस्तान का आधे से ज्यादा धन सिमट कर रह गया है ? क्या यह सच नही है कि तीन, चार हजार करोड रु० काले धन के रूप मे आज भी कुछ लोगो के हाथो मे रह गया है काले धन की बात छोडिये, इन्कम टैक्स की चोरी को छोडिये, लेकिन क्या यह सच नही है कि 700 करोड रुपया आज भी बकाया पैसे के रूप मे देश मे नही है ? अगर वाकई मे उस धन का बटवारा नही हुआ, या जमीन का सही तरीके से बटवारा नही हुआ तो समझ मे नही आता कि 50 या 100 करोड रु० देकर किस तरह से इतनी बडी समस्या का हल होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज उन लडको की बात सोचिये जिनको नक्सलाइट के नाम से पुकारा जाता है। बी० एस० सी० और एम० एस० सी० पास करने के बाद इंजीनियर बन जाने के बाद जिनको नौकरी नही मिलती। ऐमप्लायमेट ऐक्सचेंज के चक्कर लगाते-लगाते जब घर मे जाते है तो उनके सामने उनकी माँ की शक्ल नजर आती है, हाँपते हुए बाप को देखते है, छोटे-छोटे भाइयो को देखते है, उनकी

[श्री एम० एम० बनर्जी]

बहन जिसकी उम्र काफी हो चुकी है लेकिन पैसे की कमी के कारण उसके हाथ पीले नहीं हो सके हैं, तो उनमें एक विद्रोह की भावना जगती है, उनकी आँखों के सामने एक नक्शा आता है कि रेल की पटरी के नीचे या तो आत्महत्या करलें या इस समाज की पटरी को बदल दें जिसके फलस्वरूप बेकारी बढ़ रही है। यही कारण है कि देश में आज विद्रोह की रूपरेखा कुछ दूसरे तरीके की नजर आ रही है। और यह दूर तभी हो सकती है जब वाकई मे समाजवादी ढंग से हमारे देश के आर्थिक ढांचे को बदला जाये। और यह एकाधिकार को समाप्त करके ही हो सकता है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हम कहते हैं, लेकिन इससे सारी समस्यायें हल नहीं हो जायेंगी। उन देशों में जो समाजवादी देश है, चाहे वह रूस हो या दूसरा देश हो, क्या वजह है कि वहाँ पर बेकारी आज नहीं है? क्या आज कोई शख्स बता सकता है कि रूस में बेकारी है? क्या कोई बता सकता है, चाहे कितने ही दुश्मन हों रूस के, कि समाजवादी देशों ने इस समस्या को हल नहीं किया है? किस तरीके से उन देशों ने हल किया है? किस तरीके से आखिर उन्होंने हल किया है? आज वहाँ पर हर आदमी को जीने का सहारा है। हमारे देश मे उपाध्यक्ष महोदय, आज 27 करोड़ लोग ऐसे है जिनकी आमदनी 8 आने, 10 आने, 75 पैसे है। और इसी देश में बिडला साहब की आमदनी दो लाख रु० रोज की है। तो यह समाजवाद का मजाक है।

सदन में बहस करते करते यह कहा गया कि एक कमेटी बैठे। एक कमेटी बैठी हुई है उसने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की और कहा गया कि प्लानिंग कमीशन 2,000 करोड़ रु० दे ताकि बेकारी का कुछ हल निकले। इतना रुपया कहाँ से आयेगा? 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 2400 करोड़ रु० सरकार के पास आया, जो कि पहले सरमायेदारों के हाथों में था। लेकिन कुछ लोग है जिनकी मोनोपलीज़ हैं उनको सरकार अगर अपने हाथों मे नहीं लेती है तो बेकारी और गरीबी हटाओ का नारा एक नारा बनकर रह जायेगा और आप उसको अमली जामा नहीं पहना सकेंगे। इसलिये बहस की खातिर नहीं इस समस्या का आपको ज्यादा जवाब देना है क्योंकि ज्यादातर सीटें आपकी है। और ठीक है आप जीते है, सही नारे से जीते है। लेकिन लोग जब पूछेंगे कि हमारे लिये क्या लाये हो, हमारा भविष्य क्या है। तो भविष्य अगर अधकारमय लोगों का होगा फिर आप सोच सकते है कि उन लोगों का आपके प्रति क्या भाव, रुख होगा जिन्होंने आपको इस बार में चुनाव मे उदारता से जिताया है।

आज जैसा मैंने पहले कहा बेकारी और भुखमरी की दौड़ लग रही है। 1957 के पहले की हालत देखिये। उस समय जो एक मिल का मालिक था वह आज 10 मिलों का मालिक बन गया है। जो एक बंगले का मालिक था वह आज 10 बंगलों का मालिक हो गया है। लेकिन साधारण आदमी, जिसकी आमदनी 100 रुपये थी उसकी आमदनी घटकर केवल 50 रु० रह गयी है। एक आदमी जो छप्पर में रहता था वह आज फुटपाथ पर रहने लगा है और जो फुटपाथ पर रहता था वह आज बिना कफन के मरने लगा। जहाँ पर इतनी आर्थिक विषमता हो कि एक बच्चा इसलिये रोता है कि वह दूध पी नहीं सकता है, दूध का गिलास फेंक देता है, और दूसरा बच्चा इसलिए रोता है कि माँ का दूध पीते-पीते माँ के दूध के बजाय खून का कतरा उसके मुंह में आ जाता है। इसलिए एकाधिकार को समाप्त किया जाये, मोनोपलीज को नेशनेलाइज़ किया जाये और आज कम से कम लोगों को बेकारी का भत्ता

दिया जाय अगर आप वाकई में बेकारी का निराकरण करना चाहते है तो ।

लोग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा फाड देते है, कानवोकेशन ऐड्रैस में लोग जाते नही है क्योंकि वे कहते हैं कि हम डिप्लोमा लेकर क्या करेंगे ? और इसीलिये जो विद्रोह की भावना बढ रही है अगर आप उसको रोकना चाहते है तो कम से कम उनको एक तरह से बेकारी का भत्ता देना पडेगा जिससे उनको विश्वास होगा कि आज अंधेरा हो सकता है लेकिन, कल सवेरा उनका होगा । कल उनका होगा । वर्ना कोई चीज नही हो सकती है ।

गरीबी हटाओ का नारा सबने अपनाया और इंदिरा जी को दिल खोलकर जनता ने वोट दिये । इस सरकार ने जो कुछ माँगा जनता ने उदार होकर उसको दिया, कोई हीला हवाला उसने नही किया । आज जनता ने उनके दामन को भर दिया, तमाम सदनो को भर दिया कांग्रेस के मेम्बरो से । लोग आशा करते है कि प्रधान मंत्री इस चीज के बारे में सोचेंगी । आप शौर्ट टर्म प्लान लागू करेंगे । लौग टर्म प्लान कब होगी ? 10 साल के बाद बेकारी दूर हो जायेगी ? अगर आपने इस बारे मे उचित कदम नही उठाये तो मुझे तो लगता है कि कही द्रौपदी के चीर की तरह यह बेकारी बढ़ती ही न चली जाये ।

इन शब्दो के साथ मै इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और अपनी पार्टी की ओर से माँग करता हूँ कि एकाधिकार, मोनोपलीज़ हाउसेज़ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । तेल की विदेशी कम्पनियों को नेशनेलाइज़ किया जाये और बेकारी का भत्ता दिया जाये । इस भावना के साथ मै इस प्रस्ताव की ताईद करता हूँ ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही सदन मे अतरिम रिपोर्ट रखी गयी है "शौर्ट टर्म मैजर्स फौर ऐमप्लायमेट" । मगर उन्ही विषयो की ओर आप ध्यान देंगे । उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यह जो भयंकर समस्या अनएमप्लायमेट की है उसके किनारे तक भी यह रिपोर्ट नही पहुँच पा रही है । अतरिम रिपोर्ट, श्री भगवती रिपोर्ट मे कहा गया है कि अगर थोड़ा सा रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का काम और माइनर इर्रीगेशन का काम बढाया जाये तो कुछ न कुछ प्रौबलम हल हो सकती है । यह काम बहुत दिनो से चल रहा है और बराबर डा० के० एल० राव ने इसके संबंध मे कार्फी बाते भी की है, उन्होंने बारम्बार कहा है कि हजारों गाँवो का महीने मे विद्युतीकरण किया जाये । मगर उससे थोड़े से खास काट्रैक्टर्स और थोड़े से जो पहले से लगे हुये इंजीनियर्स या ओवरसीयर्स है, वही जो पहले से रुपया पाने आ रहे है उन्ही के लाभ की ओर ख्याल दिलाया गया है । अंतरिम रिपोर्ट के चौथे पन्ने के सातवें पैराग्राफ मे कहा गया है :

> "The total number of jobs has increased by 36 21 lakhs in June 1970 to 44 95 lakhs in June 1971, that is, a rise of about 24% in a year."

श्री बनर्जी ने ठीक ही कहा कि जितना ही इस प्रश्न को छोटा समझा जाता है, जितनी ही द्रोपदी का चीर खीचने की कोशिश की जाती है, उतना ही विशाल और गम्भीर यह प्रश्न बनता जा रहा है । आपने इसके लिए कुछ कोशिश की है । स्माल फार्मर्स डेवलपमेट एजेंसी और मार्जिनल प्रोग्राम एग्रीकल्चर फार्मर्स दोनो को मिलाकर आपने करीब 125 करोड रुपया दिया है, जिससे आफ टाइम से एक छोटे से किसान की आमदनी थोडी सी बढ सकती है, गाँवो मे जो मजदूर रहते है उनको थोडा सा काम मिल सकता है कैश प्रोग्रेम्स वगैरह मे । लेकिन वास्तविक प्रश्न को समुचित रूप मे छुआ भी नही गया है ।

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

आप देखिये कि सारे देश मे किस तरह से हाई स्कूलो की वृद्धि हुई है। हर दस-पाँच गाँवो को मिलाकर एक हाई स्कूल जरूर है और उसी अनुपात से मैट्रिकुलेट्स भी निकलते जा रहे है। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स अनएम्प्लायड है उनकी सख्या तो और भी ज्यादा है। आज समाज मे सबसे ऊँचे दर्जे के पढे लिखे नवयुवक अगर बेकार रहेगे तो देश मे किस तरह की भयानक स्थिति पैदा हो सकती है यह स्वय सोचने की बात है।

यह प्रश्न सचमुच गरीबी हटाओ से जुडा हुआ है। आज भी गरीबी हटाने का प्रश्न हमारे सामने विद्यमान है। यदि हम इस प्रश्न को सब बातो मे साथ लेकर चले तभी कुछ काम हो सकता है। एम्प्लायमेट के लिये जो थोडे से मेजर्स शार्ट-टर्म के दिये गये है वह केवल एक मखौल की बात है जिससे यह प्रश्न हल नही होता। माइनर इरिगेशन की बात कही गई है। इससे तो किसान को ही थोडी बहुत मदद हो सकती है, लेकिन जो पढे लिखे इजीनियर और लाखो मैट्रिकुलेट्स है उनका कोई फायदा नही होता। रूरल सैक्ट्रिफिकेशन मे इंजीनियरो को थोडा बहुत काम मिल जायेगा, लेकिन इजीनियरो की जैसी सख्या बतलाई गई है वह हर रोज बढती जा रही है। जितने भी लाइव रजिस्टर है जिनकी चर्चा रिपोर्ट मे की गई है, अगर उनमे आप 1967 और 1971 के फिगर्स को देखें तो आपको आश्चर्य लगेगा क्योकि जो भी मेजर्स उन्होने लिये है उनसे जरा भी वह इस समस्या को नही छू सके हैं। उन्होने इन्फ्रा स्ट्रक्चर की भी बात कही है। लेकिन उससे गरीब लोगो को आफ टाइम मे कुछ काम नही मिल पाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपकी एजुकेशन है जब तक वर्क प्रेरित नही की जायेगी काम की ओर प्रेरित नही की जायेगी, जैसे और देशो मे है, तब तक यह प्रश्न हल होने वाला नही है।

आज हम मे से हर लोगो के पास ऐसे पढ़े लिखे लोग आते है जिनकी दशा देखकर आँखो मे आँसू आते है। ऐसी स्थिति मे मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न पर केवल कमेटी बना देने से, उसकी इटेरिम रिपोर्ट आ जाने से ही प्रश्न हल नही होता। इस पर आपको बड़ी गम्भीरता से सोचना पडेगा। मैं श्री विभूति मिश्र को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होने देश के एक बडे प्रश्न को इस सभा मे लाकर हमको उस पर गम्भीरतापूर्वक सोचने का मौका दिया है। मै उनके प्रस्ताव की तहे दिल से ताईद करता हूँ।

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) सभापति महोदय, मे श्री मिश्र का बहुत ही शुक्र-गुजार हूँ कि उन्होने बडा अहम प्रस्ताव सदन के सम्मुख पेश किया। मै ऐसा समझता हूँ कि बेरोज-गारी की समस्या जो पढे लिखे लोगो मे है उसके सबंध मे सरकार को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। माननीय मत्री महोदय ने जो आँकडे दिये है उन्हे मै आपके सम्मुख उद्धृत करना चाहता हूँ जिससे पता लग सके कि अनएम्प्लायमेट के बारे मे हम मे कितनी सीरियसनेस है

1968 मे जो लोग एम्प्लायमेट एक्स्चेन्जेज मे रजिस्टर हुए थे उनकी सख्या थी 30,11,642, 1969 मे यह फिगर 34,23,885 तक पहुँच गया, 1970 मे यह फिगर 40,68,554 हो गई और 1971 मे यह फिगर 50,99,919 हो गया। यानि यह फिगर 9·9 परसैंट से लेकर 25·3 परसैंट तक राइज किया। लेकिन जितने लोगो ने अपने नाम एम्प्लायमेट एक्स्चेन्जेज मे रजिस्टर करवाया उनमे से कितने लोगो को एम्प्लायमेट दिया गया, उसको भी जरा आप देखें। 1968 मे 30,11,642 मे मे केवल 4,24,227 आदमियो को रोजगार दिया गया, 1969 मे 34,23,885 मे से 4,32,182 आदमियो को रोजगार दिया गया। 1970 में 40,68,554 आदमियो मे से केवल 4,47,195 आदमियो को काम दिया गया

और 1971 मे 50,99,919 मे से 5,06,973 आदमियो को एम्प्लायमेंट दिया गया है। यह स्वयं सरकार के फिगर्स है, और मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 50 परसैंट ऐसे लोग होते है जो एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज मे अपना नाम रजिस्टर ही नही करवाते। अगर हम इस मस्या को ही ले ले तो आप अच्छी तरह से समझ जायेंगे कि देश की इस सबध मे क्या स्थिति है।

मैने सेंसस की रिपोर्ट पढने की कोशिश की। सेंसस रिपोर्ट मे दिया है कि हमारे यहाँ पैदाइश की सख्या हर साल बढती जा रही है, बच्चे हर साल बढते जा रहे है। बावजूद फैमिली प्लैनिंग और दूसरे तमाम किस्म के मेजर्स अख्त्यार करने के पापुलेशन जिस गति मे बढती जा रही है उस गति मे हम कोई पोटेंशल कायम नही कर पा रहे है, एम्प्लायमेंट पोटेंशल जो हमारे यहाँ है उसमे हम सारे पुराने लोगो को ही नही खपा पा रहे है, और रोज नये अनएम्प्लायड बढते जा रहे है। एक समस्या और भी है कि देहातो के लोगो शहरो की तरफ भागते चले आ रहे है। शहरो मे कन्सेनट्रेशन हो रहा है और आज इस कन्सेनट्रेशन का नतीजा यह हो रहा है जैसाकि हम रोज सुनते है, कि नक्सलाइट पैदा हो गये। मै कहता हूँ कि अगर बेरोजगारी बढेगी या आदमी भूख से मरेगा तो क्या नही हो जायेगा? इसको हमे स्वीकार करना चाहिये और सरकार को स्वीकार करना चाहिये।

आज यह स्थिति गम्भीर होती जा रही है और इस गम्भीरता को देखकर हमे कुछ मौलिक सिद्धातो को अख्त्यार करना चाहिये। जो हमारी प्लैन बन रही है उसका जो रि-ऐप्रेजल है उसमे हमको कुछ डाइरेक्शन कायम करना चाहिये कि जहाँ तक अनएम्प्लायमेंट का सवाल है, चाहे वह पढ़े लिखे लोगो का हो या बिना पढे लिखे लोगो का हो, उसको हम कैसे हल करे और किस तरह से हम इस स्थिति को खत्म करें। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स और रखना चाहता हूँ जो 9 जनवरी के "स्टेट्समैन" मे छपे है। ग्रैजुएट अनएम्प्लायमेंट के बारे कहा गया है कि यह फिगर 67 परसैंट तक पहुँच गया है, अन्डर-ग्रैजुएट अनएम्प्लायमेंट का फिगर 69 परसैंट तक पहुँच चुका है और 92 परसैंट इजीनियर्स का फिगर पहुँच चुका है। इसी तरह मे रजिस्टर्ड जाबलेस लोगो का परसैंटेज 164 परसैंट बढ गया है। यह आपके 1970 के फिगर्स है।

मै मंत्री महोदय को इस बारे मे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहले तो यह कि आप अपनी प्लैन को रिकास्ट करे। आप रूरल एरिया और अरबन एरिया को डिफरेंशिएट करते है। चूँकि आप आज लैंड रिफार्मस करने जा रहे है इसलिए आप लैंडलेस लोगो की कोआपरेटिव बनाये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपका सारा लैंड रिफार्म का प्रोग्राम है उसको आप ठीक से चलाये। अगर आपने लैंडलेस की कोआपरेटिव नही बनाई तो "फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड" को रोक नही सकेंगे। जहाँ पर चकबन्दी हो रही है वहाँ पर इस तरह का कोई प्रोग्राम स्वीकार नही किया गया। आप यह कर सकते है कि तीन चार गाँवो मे लैंडलेस लोगो को अलग-अलग चक अलाट करके वहाँ पर उनकी कोआपरेटिव बना दे और उनको सारी सुविधाये दे ताकि वहाँ पर ठीक से आपका डेवलपमेंट का काम हो सके और लैंडलेस लोग कम से कम खेतो के मालिक बनाये जा सके।

इस तरह से आपको एक तरफ तो रूरल एरियाज मे काम करना होगा और दूसरी तरफ अरबन एम्प्लायमेंट के सवाल को भी देखना होगा। गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स मे ब्यूरोक्रेसी जिसको चाहती है, उसको नौकरी दे देती है। मै मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वह सैल बनाकर देखे कि एम्प्लायमेंट का कितना पोटेंशल क्रीएट किया गया है, कितनी जरूरत है और कितना पोटेंशल सरकार क्रीएट कर सकती है। जितने लोगो को एबजार्ब किया जा सकता

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

है, उनको एबजार्ब किया जाय। एम्प्लायमेंट के प्रश्न को ब्यूरोक्रेसी और डिपार्टमेंट्स की स्वेच्छा पर नहीं छोडना चाहिये, बल्कि नीति के अन्तर्गत एम्पलायमेंट के पोटेंशल को बढाना चाहिये।

16 hrs

देश के हर एक नागरिक को रोजी और रोटी देने की जिम्मेदारी सरकार और समाज पर है। एक शान्तिमय क्रांति द्वारा समाज को बदल कर इस समस्या को हल किया जाना चाहिये। लेकिन अगर सरकार ने इस समस्या को गम्भीरता से नही लिया और वह लोगो को रोजी और रोटी देने की व्यवस्था नही कर सकी, तो यह निश्चित समझिये कि समाज इस रूप मे नही चल सकता है, समदीय व्यवस्था नही चल सकती है। तब लोगो को बाध्य होकर नक्सलाइटस की तरफ देखना पडेगा और देश मे एक भयकर समस्या खडी हो जायेगी।

मै इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मदसौर) : सभापति महोदय, यदि देश मे बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के सबध मे कोई प्रस्ताव यहाँ लाया जाता है, तो सरकार को उसे स्वीकार करने मे कोई हिचक नही होनी चाहिए। हर पच-वर्षीय योजना से पूर्व सरकार कहती है कि उसके अन्त मे बेकारी कम हो जायेगी, लेकिन देश मे बेकारी निरंतर बढती चली जा रही है। हर एक पंचवर्षीय योजना मे बेकारी और बेरोजगारी के नाम पर काफी धन रखा जाता है, लेकिन पिछले आँकड़ो से पता चलता है कि हर पंचवर्षीय योजना के बाद बेकारों की संख्या बढ जाती है। बेकारी और बेरोजगारी की समस्या इतना भयकर रूप धारण कर रही है कि वह देश के लिए एक अभिशाप के समान दिखाई दे रही है। आज साठ हजार इंजीनियर बेकार है, अनेक डाक्टर और पायलट बेकार है। यदि सरकार इस समस्या को टालना चाहती है, उसको हल नही करना चाहती है, तो यह कहे बगैर नही रहा जा सकता है कि बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के सबंध मे उसका जो कर्त्तव्य है, वह उससे पीछे हट रही है।

मै इस संबध मे अपनी ओर से कुछ नही कहना चाहता हूँ, बल्कि चतुर्थ पचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्याकन के इन शब्दो को उद्धृत करना चाहता हूँ

> "Serious and growing unemployment among the non-technical education is a chronic problem In recent years, it has been deteriorating even faster than usual This indicated even if inadequately by the sharp rise in the number of educated on the live register of the employment exchanges The total increased from 1 4 million in June 1969 to 2 1 million in June 1971 "

सरकार द्वारा दिये गये इन आँकडो से यह सिद्ध है कि कई पच-वर्षीय योजनाओ के बाद भी सरकार इस समस्या को हल करने मे असफल रही है। बेकारी को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो के लिए एक क्रैश प्रोग्राम के नाम से सरकार ने पचास करोड रुपये की व्यवस्था की, लेकिन जब यह धनराशि ठीक ढग से खर्च नही की जाती है और उसके लिए उचित इन्तजाम नही किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि सरकार इस समस्या के समाधान की तरफ यथोचित ध्यान नही दे रही है। इसी तरह सरकार द्वारा एडुकेटिड लोगो को रोजगार देने के लिए करोड़ो रुपया रखा गया है, लेकिन वह वह ठीक ढंग से खर्च नही किया गया है।

अगर सरकार पढे-लिखे लोगो और टेकनिकल हैड्ज को काम देने के अपने दायित्व को पूरा नही करती है, तो देश मे अराजकता और

अशान्ति की स्थिति पैदा होगी। हम चाहते हैं कि देश में रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण और स्थिति पैदा की जाये। यदि देश के गाँव गाँव में कृषि-प्रधान और अन्य छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किये जायें, तो हाथों को काम मिलेगा और देश की सम्पदा बढ़ेगी। यदि हमारी योजनायें इस आधार पर बनें, तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन सरकार इस प्रकार की योजनाओं को प्रमुखता नहीं देती है।

हम देखते हैं कि योजना मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों का आपस में तालमेल नहीं है, वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा नहीं की जाती हैं। अगर मैन-आवर्ज के आँकड़ों को देखा जाए, तो पता चलता है कि जितनी श्रम शक्ति को काम में लाना चाहिए था, वह काम में नहीं आई है। देश की असंतुलित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीति के गलत होने के कारण उत्पादन घट रहा है जिसके कारण बेकारों की संख्या बढ़ रही है।

इसलिए हमने यह मांग की है कि संविधान में संशोधन करके आजीविका, रोजगार, पान के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाये। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार का साधन नहीं मिलता है, तो उसको बेकारी भत्ता दिया जाय। ऐसा करने पर ही यह समस्या हल हो सकती है। सरकार के थोथे वादों, नारों और आश्वासनों से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। अगर हम अपनी अर्थ-व्यवस्था और योजनाओं के संबंध में विदेशों का अंधानुकरण करेंगे, तो बेकारी और बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। हमारी अर्थनीति विदेशों पर आधारित न हो।

आज हमारे देश में रोजगार चाहने वाले शिक्षित और अशिक्षित लोगों की संख्या लगभग तीन करोड़ हो गई है। पचास, पचपन करोड़ के देश में तीन करोड़ आदमी काम माँगते हैं और उनको काम नहीं दिया जाता है, सरकार के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इन लोगों को काम देने के लिए उपाय किये जायें। इसलिए इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस प्रस्ताव को भी स्वीकार करने वाली नहीं है क्योंकि वह तो बेकारी और बेरोजगारी के भीषण चक्र में जनता को फंसाये रखना चाहती है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) सभापति महोदय, हमारे देश में चाहे इंजीनियर हों और चाहे डाक्टर, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट हों या वकील और चाहे गाँवों में रहने वाले साधारण आदमी हों, वे सब बेरोजगारी की बीमारी से पीड़ित हैं। सरकार ने जितने भी वादे या घोषणायें की, वे सब निर्मल सिद्ध हुई। हालत यह है कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की।

यह समस्या बहुत गंभीर है, जिसका इलाज आज तक नहीं हो सका है। मैं कुछ कंक्रीट बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरकार भले ही भगवती कमेटी बनाये या कोई दूसरी कमेटी, लेकिन उसको इस समस्या के समाधान के लिए तुरन्त कारगर कदम उठाने चाहिए। उन कारगर कदमों में से एक यह है कि सब राज्य कर्मचारियों को 55 साल की उम्र पर आवश्यक तौर पर रिटायर कर दिया जाये, ताकि नये लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। राजस्थान, और शायद पंजाब, आदि कई राज्य सरकारों ने यह नियम लागू कर दिया है। मैं मांग करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार भी इसी पैटर्न पर लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करने के लिए तुरन्त यह कदम उठाये। मेरी दूसरी मांग यह है कि आज यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कालेजिज और इंजीनियरिंग कालेजिज में

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) सभापति महोदय, सदन मे बेरोजगारी के सबधी बात हो रही है, जिसका संबध पूरे देश के लोगो के साथ है। लेकिन सदन मे कोरम नही है।

सभापति महोदय : घंटी बज रही है। .... अब कोरम हो गया है, माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखे।

श्री नवल किशोर शर्मा : मै अर्ज कर रहा था कि एजूकेशनल इंस्टीट्यूशस में चाहे यूनिवर्सिटीज हो चाहे दूसरी संस्थाएं हो, उनमे हर आदमी को जो एडमीशन मिलता है और हर आदमी हर तरह की शिक्षा लेने का अपना अधिकार समझता है इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। योग्यता के आधार पर ही हायर एजूकेशन दी जानी चाहिए और इस देश से जब हम रोजगार नही दे सकते तो फिर शिक्षा के मामले मे हमे प्रतिबंध लगाना होगा। हमको यह देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति किस ब्राच को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए उसका टेलेंट, उसका एप्टीट्यूड भी है या नही। यह बात बुरी लगती है और मुश्किल भी है क्योकि डेमोक्रेसी मे जहाँ डेमोक्रेटिक सरकार होती है उसके सामने ऐसे रेस्ट्रिक्शस लगाने मे कठिनाई होती है, पर देश के हित में यह करना आवश्यक है और जरूरी है और इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं नही जानता जाब ओरिएंटेड एजूकेशन की बात पिछले वर्षों से हम सुनते आ रहे है। हर मंत्री एजूकेशन का, हर केन्द्रीय मंत्री और राज्य सरकारो का मंत्री जाब ओरिएंटेड एजूकेशन की बात करता है। लेकिन उसके बारे मे शायद हिन्दुस्तान मे एक इंच भी शुरुआत नही की गई। तो सीरियसली इस बात को सोचना चाहिए और गंभीरता से सोच कर फेज्ड प्रोग्राम के तौर पर इस काम को हमे शुरू करना चाहिए।

तीसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। गाँवों मे बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जो गाँवो की भीड़ आज शहरों की तरफ भाग कर आ रही है उसके लिए आवश्यक यह है कि भूमि सुधार के कार्यक्रम को तेजी से से लागू किया जाय। लैंड सीलिंग की सीमा जहाँ नही कायम हुई है उसको कायम किया जाय। जहाँ कायम हुई है उसको घटाकर फालतू जमीन बेरोजगार लोगों को दी जाय।

एक माननीय सदस्य : कहाँ है जमीन।

श्री नवल किशोर शर्मा : जमीन है। जमीन बहुत है। हमारे यहाँ बहुत जमीन है। तो मै निवेदन कर रहा था कि वह किया जाना चाहिए और अब सरकार को उस काम को प्रायरिटी बेसिस पर फेज्ड प्रोग्राम के तौर पर करना चाहिए।

एक शब्द और कहना चाहूँगा। मैसिव रोड कास्ट्रक्शन प्रोग्राम को और विलेज इंडस्ट्रीज प्रोग्राम को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। उसके जरिए से गाँवो की हालत सुधरेगी। जो पढा लिखा तबका गाँवो से भाग कर शहरो की तरफ आता है उसको थोडी सी दिलचस्पी होगी गाँवो मे रहने की और उद्योग धंधे करने की। श्रम का महत्व कायम किया जाय, यह बहुत आवश्यक है। इन्ही शब्दो के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सरकार मे बैठे हुए मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुछ काक्रीट बात कहे, आँसू पोछने वाली बात सुनते-सुनते तो बहुत समय हो गया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अनएम्प्लायमेंट के बारे मे बहुत समय पहले हमने एक पालिसी बनाई थी कि एक फैमिली मे एक आदमी से ज्यादा को उद्योग नही मिलना चाहिए जब तक कि हर फैमिली मे एक-एक आदमी को उद्योग न मिल जाय। मगर यह बात सब भूल जाते है और यह कांग्रेस का रेजोल्यूशन भी है। इसके बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि एक ही फैमिली में उसी के पास जमीन भी है, उसी को

दुकान है, वही पोलिटिक्स मे भी है, उसी के घर से एम० एल० ए० भी है, उसी के घर मे कई-कई लोगो को नौकरियाँ मिल जाती हैं और न सिर्फ यही बल्कि उनके घरो की स्त्रियो को भी नौकरियाँ मिल रही है। गवर्नमेंट से मै पूछना चाहता हूँ कि जो बात आपने तीन साल पहले कही जबकि कॉग्रेस का बटवारा हुआ, तब कही, उसके बाद बाद से कभी इसकी जाँच की या नही ? इस समय में जितनी नौकरियाँ मिली है वह क्या उन घरो में गई है जहाँ नौकरियाँ नही है ? ऐसा नही है। आज गरीबो को कोई नौकरी नही मिलती है और जो असर वाले है उनको चार-चार, पाँच-पाँच नौकरियाँ एक-एक घर मे मिल रही है। तो यही मेरा निवेदन है कि इसमे जाँच पड़ताल की जाय। एक कमेटी इसके लिए मुकर्रर की जाय। जब तक ऐसा नही करेगे तब तक यह चीज होने वाली नही है और चारो तरफ इससे बेचैनी बढ रही है।

यह कहा जा रहा है कि जमीन का बटवारा कर दिया जाय। मै यह कहना चाहता हूँ कि दूसरे मुमालिक मे जमीन पर सिर्फ 12 से 20 प्रतिशत लोग काम करते है। हमारे मुल्क मे 80 प्रतिशत लोग जमीन पर काम करते है। जब प्लानिंग शुरू हुई उस वक्त यह कहा गया कि जमीन पर जो टेंशन है, तनाव है, उसको घटाकर 80 से 50 प्रतिशत कर दिया जाय। यानी 50 प्रतिशत से ज्यादा जमीन पर काम करने वाले न हो। लेकिन अब तो हर आदमी ने एक स्पीच देना शुरू कर दिया है कि पूरे लोगों को जमीन पर बसा दिया जाय। यह अनएकोनामिक बात हो रही है। जमीन पर ज्यादा लोगो को न रख कर उन लोगो को इंडस्ट्रीज मे काम दिया जाय। जब तक इडस्ट्रीज में सबको काम नही दे सकते है उस वक्त तक एक फैमिली में एक आदमी को नौकरी मिले, इसका प्रबन्ध होना चाहिए।

सभापति महोदय : दो तीन नाम रह गए है, वह लोग आखिर मे जब मिनिस्टर बोल लेंगे, उस वक्त कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सभापति महोदय, माननीय मिश्र जी ने जो यह सकल्प सदन मे रखा था उस पर काफी चर्चा हुई और बहुत से सदन के सदस्यो ने इसमे भाग लिया। हम उनके आभारी है कि उन्होंने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए है। जैसा कि सदस्यो को भली प्रकार ज्ञात है, सरकार इसकी ओर काफी सचेत है और प्रत्येक प्रकार के कदम उठाने की कोशिश कर रही है जिससे कि हम बेरोजगारी को खत्म कर सकें। यह सभी जानते है कि कॉग्रेस पार्टी ने पिछले वर्ष जब एलेक्शन लड़ा तो अपने मैनिफेस्टो मे इस बात को कहा कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बेकारी को मिटाएगे और उसके निमित्त हमने काफी कदम उठाये है जो मै आपके सामने अभी रखूँगा। इसके अलावा भी आप देखे कि जब से हमने योजनाओ को अपने देश मे लागू किया है सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि उन योजनाओ के द्वारा काफी से काफी लोगो को नौकरिया दी जाएँ जिससे कि इस समस्या का हल निकल सके। लेकिन देश हमारा बहुत बडा है। जनसख्या भी काफी है और जो हमारे पास सीमित साधन है उन्ही के अनुसार हम यह प्रयत्न कर सकते है। पिछली तीन योजनाओ मे हमारे यहाँ करीब 3 करोड 10 लाख लोगो को नौकरियाँ दी गई। लेकिन इसी बीच मे यह भी आपको जान कर परेशानी होगी कि 3 करोड 80 लाख और बेरोजगार हमारे बीच मे आ गए। उनकी व्यवस्था हमे करनी पडी· · ·

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : साल मे एक करोड आदमी ज्यादा होता है। 15 साल मे 15 करोड आदमी ज्यादा हुए।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह ठीक कह रहे

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

है। लेकिन जो पढाई की सुविधाए हुई है और जो टेकनिकल सुविधाएं पैदा की गईं इसकी वजह से हमारे बीच मे उन लोगो की सख्या ज्यादा हो गई जो कि पढ़े लिखे और शिक्षित थे जिनको कि हम नौकरी देने मे उतना नही कर पाए जितना कि करना चाहते थे। इसका कारण भी है। आप देखे कि पिछली पंच-वर्षीय योजना मे हमारे देश मे कुछ विपत्तियाँ आई। हमारे ऊपर दो आक्रमण हुए। फिर सूखा भी पड़ा, दो साल तक हमे परेशानी उठानी पडी। हमारे यहाँ की इकोनामी करीब-करीब नष्ट सी होने लगी। चूंकि पैदावार मे गिरावट हुई इस वजह से चीजो के दाम बढ़ गए। और साथ-साथ हमे कुछ माल की कमी पड़ गई, इस वजह से जो हमारे उद्योग चल रहे थे, उनमे शिथिलता आ गई और बेकारी बढ़ गई। इसी प्रकार से आप यह भी देखेगे कि गवर्नमेंट भी इस समस्या का सामना करने के लिए खामोश नही बैठी रही, हमारी ओर से इस तरफ काफी सतत् प्रयत्न होता रहा है।

काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुआ है कि बेकारी बढ़ रही है, लेकिन अभी तक हम कोई ऐसे आँकड़े नही पा सके है, जिसमे हमको एक्चुअली मालूम हो सके कि कितनी बेकारी बढी है। श्री नरसिह नारायण जी पाडे ने कुछ आकड़े दिये हैं, मै उनको मानता हूँ, लेकिन इनकी सत्यता को प्रमाणित नही किया जा सकता।....

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : लेकिन आपके पास आंकड़े होने चाहिएँ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमारे डी० जी० ई० टी० ने इस संबंध मे सैम्पुल सर्वे कराया था, उससे यह मालूम हुआ कि उनमे से 50 फीसदी लोग जरूर ऐसे है जो बेरोजगार हैं। 42·3 परसैंट लोग ऐसे थे जो कही न कही नौकरी में थे। उन्होने अपना नाम इस लिए रजिस्टर कराया हुआ था कि कही अच्छी नौकरी मिले तो उसको छोड़ कर दूसरी जगह चले जायँ। इनके अलावा 7 परसैंट लोग ऐसे थे, जो स्टूडेन्ट्स थे उनका नौकरी का ख्याल नही था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होने बताया कि हम पढ़ रहे है, रजिस्टर इस लिए करा दिया है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाय तो चले जायेंगे।...

श्री फूल चन्द वर्मा (उज्जैन) : आप शब्दो के जाल मे उलझा रहे हैं।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमे भी उतनी ही चिन्ता है, जितनी आपको है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली-शहर) : बहुत से लोग ऐसे भी है जिन्होने अपने आपको रजिस्टर ही नही कराया है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह सही है, हम इस बात को नजरअन्दाज नही कर सकते कि ऐसे भी लोग है, जिन्होने अपने आपको रजिस्टर नही कराया है।

श्री फूल चन्द वर्मा : 3 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे है, जिनके नाम रजिस्टर्ड नही है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : आप कैटेगारिकली आँकड़े रख रहे हैं, हमें ताज्जुब ही रहा है। हमारे पास तो आँकड़े नही है...

श्री फूल चन्द वर्मा : मैं आपकी रिपोर्टों से ही कह रहा हूँ, मेरे घर के आँकड़े नही हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपके हिसाब से बेकारी बढ़ी हैं या घटी है?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : बेकारी बढ़ी है, इसीलिये सरकार को बड़ी चिन्ता है। हमने इस संबध में जो कदम उठाये हैं, उन्हें भी मैं आपके

सामने रखूंगा। इसी लिए हमने श्री दाँतेवाला की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की थी ताकि मालूम हो सके कि देश में कितनी बेकारी है, हमारे सामने जो स्टेटिस्टिक्स है, उनको दुरुस्त कर सकें। उन्होंने कुछ गाइडलाइन्ज दी है, जिनके आधार पर हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में कितनी बेकारी है और उसको किस प्रकार से खत्म करें। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यद्यपि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं थी, तो भी उसके मायने यह नहीं थे कि हम अपने रास्ते से हट जायँ, हम लगातार इस बात की कोशिश करते आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम-धन्धे पैदा हों ताकि नौकरियों की तादाद बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय : यह बतलाइये कि क्या कोशिशें की गई हैं ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : अधिक से अधिक लघु उद्योग और मझौले उद्योगों को बढाने की कोशिश की जा रही हैं। टैकनीकल परसोनल को टैकनिकल नौ-हाऊ प्रदान करने की कौशिश की जा रही है जिससे वे अपने पैरो पर खड़े हो सकें और स्वयं कोई उद्योग चला सकें। नैशनलाइज्ड बैंकों की तरफ से सहूलियतें दी जाने लगी हैं। अगर कोई आदमी अपना उद्योग चलाना चाहता है तो नैशनलाइज्ड बैंकों से काफी पैसा मिल रहा है····

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : आप नेशनलाइज़ड बैंकों की बात कर रहे हैं, इन बैंकों से कुछ नही मिलता है। यह बिल्कुल गलत बात है, आप एक भी एक्जाम्पिल दें, किसी भी एजूकेटेड अनएम्पलाएड यूथ को किस बैंक से मिला है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : सरकार की तरफ से बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि इन्जीनियरों या डिप्लोमा होल्डरों को·····

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : हमे निर्देश नही चाहियें, हमें रिसोर्सेज़ चाहिये।

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल (महासमुन्द) : वे सिक्योरिटी माँगते है, उनके नियम बहुत सख्त है।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : सिक्योरिटी ही नही परसेन्टेज भी माँगते हैं।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : आप इस बात को फाइनैन्स मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाइये, तो शायद इसका समाधान हो सके।

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल : उनको एम्प्लायमेंट मिले, यह आपकी भी जिम्मेदारी है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मै अपनी जिम्मेदारी से अपने को अलग नही करता हूँ। हमें जब भी मालूम होता है कि फलाँ जगह समस्या जटिल है, हम जितने भी मंत्रालय है, उनको बार-बार इस बात के लिये कोचते हैं कि ऐसी योजनायें चलाई जायें, इस प्रकार से काम किया जाय, जिससे समस्या का हल निकल सके।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो लोग धन्धा शुरू करते है, उनका माल कौन खरीदेगा ? क्या इसकी कोई व्यवस्था है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मार्केटिंग की व्यवस्था भी की गई है।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : आज कम्पीटीशन में वे लोग जिन्दा नही रह सकते है। सारा खर्चा लक्जरी गुड्स में हो रहा है, लेकिन उनके पास तो माल खचाखच भरा है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमारी तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि बेकारी दूर की जाय, उनको रोजगार दिया जाय। अभी पैट्रोल की बात चली थी, पैट्रोल पम्प्स के बारे में तय

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

हुआ है कि उनको दिये जायेगे जो ग्रेजुएट्स होगे, पढे लिखे होगे। इसी तरह से जहाँ-जहाँ समस्या ज्यादा जटिल है, वहाँ वहाँ कोशिष की गई है। स्माल फार्मर्स डवेलपमेंट एजेन्सीज कायम की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगो को काम मिल सके। अन्दाजा ऐसा है कि इन एजेन्सीज से पचास हजार लोगो को काम मिल सकेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपाल गज) आप स्टेटिस्टिक्स बता रहे है, आप बतलाइये कि किन किन स्टेट्स मे कितना रोजगार मिला है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इसके लिए कोशिश की जा रही है। भगवती कमेटी इसीलिये बनाई गई है ताकि वह इस मामले की डिटेल मे जाय। उन्होने कुछ सुझाव भी दिये है जिन पर गवर्नमेंट विचार कर रही है और जल्द से जल्द उनको कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही है।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : सरकार भी इन छोटे उद्योगो का माल नही खरीद रही है, सरकारी दफ्तरो मे भी उनका माल नही खरीदा जाता है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैने कहा है कि इसकी व्यवस्था की जा रही है। जो माल वह बनाये, उसको बिकवाया जाय। सरकार इस बारे मे कोशिश कर रही है।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे · नागपुर के पास कोराडी थर्मल पावर स्टेशन मे एक करोड रुपये के माल की आवश्यकता है। अगर लोकल लोग देना चाहे तो उनसे नही लिया जाता, बम्बई से कोटेशन मगाई जाती है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इसी प्रकार से एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिये भी काफी कोशिश की जा रही है, हमारी इस योजना से 20 हजार से अधिक लोगो को रोजी मिल सकेगी। रूरल वर्कस प्रोग्राम से भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि काफी लोगो को काम मिल सकेगा। ड्राई फार्मिंग से 6 से 8 हजार लोगो को काम मिल सकेगा। एग्री सर्विस सेन्ट्र्स खोले जा रहे है और उम्मीद की जाती है कि 50 हजार लोगो को काम मिल सकेगा। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इस दिशा मे बराबर कोशिश कर रही है। पिछले साल भी आपने देखा होगा और इस सत्र मे भी देखा होगा कि 50 करोड रुपये की व्यवस्था इसलिये की गई है कि हर जिले मे एक हजार आदमियो को रोजी दी जाय। अभी जैसा मैने आपके सामने रखा कि राज्य सरकारो को हिदायत दी गई है कि जहाँ बेरोजगारी है वहाँ कम से कम एक खानदान के एक आदमी को जरूर रोजी दी जाये· (**व्यवधान**)

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : क्या इसके लिए आपने कोई जाच मुकर्रर की है कि सचमुच एक घर मे एक आदमी को नौकरी है या नही ? · (**व्यवधान**)

श्री बाल गोविन्द वर्मा पहले आप बतलाइये कि राज्य सरकारो पर आप विश्वास करेंगे या नही ? क्या हर चीज केन्द्रीय सरकार ही अकेले कर लेगी ? तमाम कामो को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो के द्वारा करवाती है। राज्य सरकारो को निर्देश दे दिये गये है कि जहाँ बेरोजगारी है, प्रत्येक घर मे कम से कम एक आदमी को रोजगार दिया जाये। · (**व्यवधान**)· ·

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय अगले 6 महीने मे बेकारी कितने प्रतिशत घट जायेगी ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा . इस तरह की डिटेल्ड इफार्मेशन देना बडा कठिन है। आप

भी अगर मेरी जगह होते तो नही दे सकते। यह कहना तो बडा आसान है लेकिन उसको करना आसान नही है। तो मै केवल यह बता रहा था कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इसके लिये काफी प्रयत्न की जरूरत है। इसके लिये सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है जो लोग सरकार की नीयत पर शक करते है उन्हे मै बताना चाहता हूँ कि चौथी योजना मे करीब 24,398 करोड़ की व्यवस्था थी लेकिन उसको बढ़ाकर 24,882 करोड की व्यवस्था की गई जिससे कि तमाम योजनाओ को चला करके बेकारी को दूर किया जा सके। इस प्रकार से पूरी कोशिश इस बात की की जा रही है। 25 करोड की व्यवस्था इस बात के लिए भी की गई कि किस प्रकार से पढे लिखे लोगो की बेरोजगारी को दूर किया जाये। शहरो मे भी इस प्रकार के काफी बेरोजगार लोग है जिनको रोजगार देने का प्रयत्न किया जा रहा है। (**व्यवधान**)··

श्री फूल चन्द वर्मा : जब तक आदमी बेकार रहे, आप उसको बेकारी भत्ता देंगे या या नही ? ··(**व्यवधान**)··

सभापति महोदय : इस तरह से अगर कोई यहाँ से उठकर क्वैश्चन कर देता, कोई वहाँ से उठकर क्वैश्चन कर देगा और आप ईल्ड करते चले जायेंगे तो हम कुछ नही कर सकते है। आप ईल्ड नही करेंगे तभी कुछ होगा। एक आदमी सवाल करे, उसका जवाब भी नही मिले और दूसरा आदमी सवाल करने लगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य बीच-बीच मे एन्टरप्ट करते है तो रुक जाना पड़ता है—यह स्वाभाविक ही है।

सभापति महोदय : जब आप ईल्ड करेंगे तो हम भी चुप रहेंगे।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : तो इसके लिए सारे प्रयत्न किये जा रहे है। प्लानिंग कमीशन भी इस पर बहुत जोर दे रहा है। उन्होंने निर्देश दिये है केन्द्रीय मंत्रालयो को और राज्य सरकारो को कि कोई योजना चलाई जाये तो उसमे इस बात का ध्यान रखा जाय कि अधिक से अधिक लोगो को रोजगार मिले। इस प्रकार हर तरह से प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगो की बेकारी को दूर किया जाय लेकिन यह सारे प्रयत्न, जो हमारे पास साधन है उन्ही के अन्तर्गत किये जा सकते है।

यहाँ पर समाजवादी देशो का जिक्र किया गया तो उनके साधन बहुत है और उनकी आबादी कम है। वे काफी विकसित देश है और हम अभी उस स्तर तक नही पहुँचे है। लेकिन यह हमारा प्रयत्न जरूर है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) क्या चीन मे भी आबादी कम है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : चीन के बारे मे हमे पता नही क्योकि वहाँ से खबरे नही आती है इसलिए हम चीन के बारे मे कुछ नही कह सकते।· (**व्यवधान**)

ऐसी स्थिति मे मै माननीय मिश्र जी से प्रार्थना करूँगा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी खत्म करे इसलिये वे अपने इस सकल्प को वापस ले लें।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : अभी पिछले बजट मे सरकार ने 50 करोड रुपये की व्यवस्था की थी बेकारी को दूर करने के लिए तो उस सिलसिले मे मै जानना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकारो से कोई रिपोर्ट आई है और इस बात को देखा गया है कि उस रुपए का प्रापर यूटिलाइजेशन हुआ है या नही ? मेरी सूचना यह है कि 50 करोड रुपया जो दिया गया उसका तमाम स्टेट्स मे गलत इस्तेमाल हो रहा है। वह सारा का सारा रुपया गलत तरीके से

[श्री सरजू पाडे]

खर्च किया जा रहा है। तो क्या केन्द्र ने उनको कोई डायरेक्टिव दिया था कि उस रुपए को कैसे खर्च किया जाये और आपने उस रुपए के यूटिलाइलेशन की कोई रिपोर्ट मंगाई है ? यदि हाँ, तो आपकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : 50 करोड रुपया जिसकी स्वीकृति आपने यहाँ पर दी थी उसके बारे मे राज्य सरकारो को निर्देश दिए गए थे कि छोटी-छोटी पानी की योजनाओ, जैसे नाली इत्यादि ठीक कराने मे लोगो को काम दें या सडकें बनायें और जहाँ तक हमारी जानकारी है वह पैसा उन्ही पर खर्च किया जा रहा है। फिर भी सरकार विचार कर रही है कि इस पैसे का और अच्छा सदुपयोग किस तरह से हो सकता है।

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : मै जानना चाहता हूँ कि बेकारी खत्म करने के लिए जो पर्मिट, लाइसेंस और लोन दिए जा रहे है उनमे जो गड़बड़ी होती है उसकी रोकथाम करने के लिए आप क्या कर रहे है ?

सभापति महोदय : यह प्रश्न यहाँ पर पैदा नही होता।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूँ कि जितने स्टेप्स इन्होने बयान किये हैं उनसे भूत मे कितना रोजगार दिया गया और भविष्य मे कितना रोजगार देने की व्यवस्था है ? मत्री महोदय यह बता दें तो हम समझें कि कहाँ तक बेकारी कम हो सकती है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : तिवारी जी ने जो प्रश्न किया है, जहाँ तक आँकड़ो की बात है, आँकड़े मेरे पास नही है कि कितने लोगों को नौकरी मिल गई है लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि हर योजना के अन्तर्गत कितने कितने लोगो को नौकरी मिल सकेगी उसकी व्यवस्था की गई है और वह मैने आपके सामने रखा · · (**व्यवधान**) · · ·

श्री डी० एन० तिवारी : वह तो बीस दफा यहाँ पर दोहराया गया है।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) · 50 करोड़ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट मे साढे 12 लाख रुपए के हिसाब से दिया गया था क्रेश प्रोग्राम के लिए। इसमे बीस परसैंट एजूकेटेड अनएम्प्लायमेट पर खर्च करने की व्यवस्था है और बाकी 80 परसेंट अनएजूकेटेड अनएम्प्लायड पर खर्च किया जायेगा तो मै जानना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत कितने एजूकेटेड लोगो को काम पर रखा गया ?

दूसरी बात यह है कि एक जिले मे सेन्ट्रल गवर्नमेंट का क्रेश प्रोग्राम भी लागू है और मार्जिनल फार्मर्स की स्कीम भी लागू है और उसके अतर्गत भी सड़कें बनाने की व्यवस्था है। तो यह डुप्लीकेशन क्यो हो रहा है ? यदि एक तहसील मे मार्जिनल फार्मर्स प्रोग्राम लागू हो तो वहाँ पर क्रेश प्रोग्राम को भी क्यो लागू किया जाये ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह जो आपने कहा है इस सिलसिले मे राज्य सरकारो को निर्देश दिए गए थे कि केन्द्रीय सरकार से उनके द्वारा क्या काम होने थे और वह काम कराया जा रहा है। अभी मेरे पास आँकड़े नही है कि राज्य सरकारो ने कितने शिक्षितो को काम दिया लेकिन यह बताया गया है कि एक हजार आदमी हर जिले मे ले लिए जायेंगे जिनको नौकरी दे दी जाएगी।

डुप्लिकेशन के बारे मे आपने जो बात कही उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हम नही चाहते कही पर डुप्लिकेशन हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके।

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या आप नौकरी पाने के अधिकार को प्रदत्त मौलिक अधिकारों मे सम्मिलित करेंगे ?

सभापति महोदय : यह सवाल यहाँ पैदा नहीं होता ।···(**व्यवधान**)····

एक माननीय सदस्य : आप बताइये न । हाँ या ना कहिए ।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें यह विदित है कि हथकरघे के उद्योग में जहाँ तकरीबन एक करोड़ लोग आज काम कर रहे हैं, इस देश में फिलहाल ऐसी परिस्थिति है कि मिलों के कम्पटीशन की वजह से वे दिन ब दिन बेकार होते जा रहे हैं। और बावजूद अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के वह रंगीन साड़ियों के बारे में जो प्रतिबंध लगाना चाहते थे वह अभी तक नहीं लगाया गया इसीलिए हथकरघे के लोग दिन ब दिन बेकार होते जा रहे है और भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं । इसका कोई इलाज करने का सरकार का विचार हैं या नहीं ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है कि कुछ लोग बेकार होते जा रहे हैं कम्पटीशन की वजह से हम उनकी भावनाओं को संबंधित मंत्रालय को भेज देंगे जिससे उस बात पर गौर किया जा सके ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास डाटा नहीं है । सरकार द्वारा नियुक्त भगवती कमेटी की रिपोर्ट में जो डाटा निकला है, सही या गलत, उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । उसमें लिखा है : "Out of the total number of job-seekers, i. e. 44·95 lakhs, as many as 20·53 lakhs were educated persons, i. e., matriculates and above, while the number of engineering and diploma holders was about 65,000."

तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास डाटा नहीं है, लेकिन इस भगवती कमेटी के पास जो कि सरकार ने बनायी, इसके पास डाटा कहाँ से आ गया ? आज ही हम लोगों को यह रिपोर्ट मिली है । सरकार के पास बहुत पहले जा चुकी है । इस रिपोर्ट पर 11 फरवरी, 1972 को दस्तखत हुए और सरकार को दी गयी ।

दूसरी बात यह कि हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं 16 मार्च को अपने व्याख्यान में कि :

> "But the two major programmes for employment in the rural areas and for the educated unemployed which were introduced in the last budget could not be given proper shape for some time; and actual expenditure is likely to fall short of the budget provision of Rs. 75 crores. Once again our experience in the current year highlights the fact that the momentum of progress cannot be kept up merely by provision of finance. Timely preparation and selection of projects and speedy implementation are equally important."

रुपया दिया और सरकार ने खर्च नहीं किया । यह सरकार का कसूर है । वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में इस बात को कबूल किया है ।

दूसरी बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार कहती है कि हमारे पास साधन सहूलियत सीमित है । मैं मंत्री जी से कहूँगा कि एक किताब है "RED CHINA TODAY, The other Side of the River, by Edgar Snow."

उसको वह पढ़ें कि चाइना ने किस तरह से अपने यहाँ अनएम्प्लायमेंट के सवाल को हल किया है । अभी हाल में, एक महीना हुआ पुस्तक के लेखक का देहान्त हो गया है। चाइना के बारे में उन्होंने लिखा है । अगर हमारे देश में जो बेकारी और भुखमरी है, एक दूसरे का गला काट रहे है, लूट रहे हैं, और यह डेमोक्रेसी

[श्री विभूति मिश्र]

हमको अगर अन्न, पानी नही दे सकती तो मुझे ऐसी डेमोक्रेसी नही चाहिये । क्यो कि मै कहता हूँ कि सविधान हमारे लिये है, हम सविधान के लिये नही है । अगर यह कास्टीट्यूशन हम को अन्न नही देता, पानी नही देता, सरकार हमारे लिये काम नही कर सकती तो हमे ऐसी कास्टीट्यूशन नही चाहिए । मै किसी आदमी का नही, बल्कि देश का वफादार हूँ । देश के काम के लिये मैं यहाँ चुनकर आया हूँ । इसलिये मत्री जी इस बात का ध्यान रखे । मैने उस दिन भी कहा था कि मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिये कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर आना चाहिये । आज देश का बर्निंग सवाल है, कही जाइये, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच मेरे पास है, जहाँ-जहाँ चुनाव के दौरे पर गयी उन्होने कहा कि बेकारी की समस्या जबरदस्त है देश के सामने । जैसे हमने पाकिस्तान से लडाई की, दूसरे देशो से लडाई करेंगे, उसका जवाब हम दे सकते है, लेकिन अपने घर के अन्दर जो हमारी बेकारी है उसका जवाब हमारे लिये देना बहुत जरूरी है । अगर नही देंगे तो जिन्दा नही रहेगे ।

मत्री जी कहते है कि सीमित साधन है । मै पूछता हूँ कि एक वोट हमारे प्रेसीडेन्ट को है और एक वोट जो बेकार है उसको भी है, कोई भी दो वोट देने नही जाता है । तो जो बेकार की हालत है उस तरह की हालत हमारे राष्ट्रपति की हालत नही है। दोनो के चित्र को मिलाइये । सीमित साधन का बटवारा कैसे करेगे । जो हमारी राष्ट्रीय इन्कम है उस का बटवारा ठीक से होना चाहिये । और जब तक नेशनल इन्कम का बटवारा ठीक से नही होगा तब तक हम जिन्दा नही रह सकते । इस सदन के द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि भारत मे साधन सीमित नही हैं बल्कि उनका बटवारा ठीक से नही होता है । कोई खाते-खाते मरता है, कोई बिना खाये मरता है ।

हम लोग जानते है कि नेशनेलाइजड बैंक्स की क्या हालत है, आपको शायद पता न हो क्यो कि आप तो मंत्री हो गये है, लेकिन हम जानते है कि किस तरह से रुपया मिलता है । नही मिलता है । इसमे सुधार कीजिये । यदि आपने बेकारी और गरीबी की समस्या को दूर नही किया तो चुनाव से हम नही जीतेंगे । रशिया मे भी लोग जीत जाते थे, और जब लोगो का काम पूरा नही हुआ तो ड्यूमा को उठा कर फेक दिया लेनिन ने और वहाँ दूसरी सरकार बन गयी । इसलिये आप अध्ययन करे और प्रधान मंत्री को बताये ।

मै समझता हूँ कि प्रधान मत्री की इस कार्य को करने की इच्छा है, दिल है, लेकिन जो साधन है, जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि हम साधन रखते है लेकिन उसको काम मे नही लाते, तो क्या करेंगे । जो साधन आप के पास है उनको काम मे नही लाते ।

आपने पैट्रोल पम्प की बात कही । मै बताना चाहता हूँ कि एक आदमी नौकरी भी करता है और पैट्रोल पम्प भी ले रखा है । एक साहब इंजीनियर है । इसलिये इनका भी ख्याल रखिये । अगर इस सवाल को आप हल नही करेगे तो ब्यूरोक्रेसी आपको खा जायेगी, आप देखे कि ब्यूरोक्रेसी सरकार को खा जायेगी, जनता को नही खायेगी । जनता ऐसी उभरेगी कि सरकार को भी खा जायेगी । और ब्यूरोक्रेसी को भी खा जायेगी । देखिये पूर्वी बगाल मे खा गयी । इसलिए आप इस काम को करें । भगवती कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट मे कहा है कि हम दो साल मे 40 लाख आदमियो को काम देंगे । वह कहाँ से यह डाटा लाये ? तो आप इसको सिमप्लीफाई कीजिये और लोगो को काम दीजिये । अगर काम नहीं देंगे तो लोग चुप नही बैठे रहेंगे ।

आप ने कहा है कि इस प्रस्ताव को मैं वापस ले लूं। आप के सीनियर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मेरे प्रस्ताव मे जो "तुरन्त" शब्द है इस को वापस ले लूं। अगर मैं "तुरन्त" शब्द को वापस ले लूं तो सरकार क्या कदम उठाएगी? जो आप का जवाब है वह बडा ही असंतोषपद है। आप मेरे प्रस्ताव को पढिये, जो शब्द कहिये उसमे संशोधन करे लेते है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव को पास नही करते है तो जनता मुझ से क्या कहेगी कि साहब आपने बात तो कही बेकारी को दूर करने के लिए और उसके लिए प्रस्ताव भी रखा लेकिन मंत्री जी ने कह दिया तो प्रस्ताव हटा लिया। आखिर हम लोग भी चुन कर आये है, जनता की बात को समझते है। यह नही है कि मिनिस्टर नही है तो हम मे अक्ल नही है। जो लोग आज गवर्नमेंट मे है वह दो शपथ लेते है। एक शपथ वह मेम्बर की हैसियत से लेते है और दूसरी शपथ वह आफिस मे आते वक्त लेते है। लेकिन जो शपथ हम सदस्य के नाते लेते है वह असली शपथ है क्योंकि जनता हमको चुन कर भेजती है। हम संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते है और संविधान के डाइरक्टिव प्रिंसिपल्स मे है कि हम लोगो को रोजी देंगे। हम देश मे समाजवाद का नारा लगा रहे है। आज कल तो अमीर भी समाजवादी होता है, गरीब भी। आज समाजवाद की परिभाषा नई हो गई है। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उस समय गाँधीजी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हिन्दुस्तान मे बडा समाजवादी मै हूँ। लास्ट फेज मे गाँधी जी और नेहरू जी की जब बात हुई तो उन्होने जो बतलाया कि वह कैसा समाजवाद चाहते है, वैसा ही समाजवाद मैं चाहता हूँ। गाँधी जी ने कम्यूनिस्टो से कहा कि मै तुम से ज्यादा समाजवादी हूँ, और कम्यूनिस्टो ने स्वीकार किया कि हाँ, आप हम से ज्यादा समाजवादी है। (व्यवधान)

इसलिए मै सरकार से कहूँगा कि सीनियर मिनिस्टर ने मुझ से कहा था कि प्रस्ताव मे से "तुरन्त" शब्द हटा दो। अब जो कुछ वह कहेंगे वह तो मुझको मानना ही पडेगा पार्टी डिसिप्लिन की वजह से। वह आज यहाँ पर नही है। लेकिन आज आपको देखना होगा कि किस तरह की बेकारी देश मे है। मेरे पास रोज चिट्ठियाँ आती है कि अगर हमको काम नही मिलेगा तो हम भाग कर रेल से कट जायेंगे। यहाँ पर मेरे थैले मे भी इस तरह की चिट्ठी पडी होगी। जिसमे वह लिखते है कि फलाँ मिनिस्टर से कहो, फलाँ आदमी से कहो। नतीजा यह हो गया है कि हम लोगो का जीना हराम हो गया है। आज जो सरकार मे आई० ए० एस० और आई० सी० एस० लोग बैठे हुए है उनके चाचा, भतीजे, नाना, काका के आदमियो को ही नौकरी मिलती है, आम आदमी को काम नहीं मिल रहा है। अगर इस देश को बचाना है, प्रजातन्त्र को बचाना है, सरकार को बचाना है तो आप प्रभावी कदम उठाकर बेकारी को दूर कीजिए नही तो जैसे आप को ला कर बिठलाया है वैसे ही जनता हटा भी सकती है। उसने आपको चुन कर भेजा है इसी से मालूम होता है कि उसमे कितनी बेचैनी है बेकारी को दूर करने के लिये। आप उसको दूर करके ही इस स्थिति को सुधार सकते है।

MR CHAIRMAN There are two amendments, moved by Shri C K. Chandrappan He is not here I will put the amendments to the vote of the House

The question is

That in the resolution,

for "effective" *substitute*

"radical economic and practical" (1)

That in the resolution—

add at the end

"and to bring forward a scheme for providing unemployment relief to all those who are at present involuntarily unemployed" (2)

The motion was negatived

सभापति महोदय : आप प्रस्ताव का वापस लेते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : अगर सरकार आश्वासन दे कि हम मनसा, वाचा, कर्मणा से इसके लिए कोशिश करेंगे कि इस देश से बेकारी दूर हो तो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा . मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूँ और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है सरकार का भी वही मत है कि जितनी जल्दी हो सके बेकारी को हम दूर करेंगे । इसके लिए पूरे कदम उठाए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह काम हो । इसके साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

MR CHAIRMAN Is it the pleasure of the House that he may withdraw ?

SOME HON MEMBERS Yes

MR CHAIRMAN So, at the pleasure of the House, it is withdrawn

SHRI BIBHUTI MISHRA I withdraw the Resolution

The Resolution was, by leave, withdrawn

16·54 hrs

RESOLUTION *Re* INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOUR POLICY

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) Mr Chairman, Sir, I beg to move the following Resolution

"This House is of opinion that in the interests of overcoming industrial stagnation, developing self reliance and expanding social justice for the working class, the Government of India should immediately adopt a new industrial relations and labour policy ensuring rights of trade union recognition, collective bargaining without third-party interference, removal of curbs on the right to strike and effective workers' control over production at different levels"

I have been motivated partly to bring forward this resolution because of the slogan which has suddenly become fashionable in this country emanating from the highest quarters namely that there should be a moratorium on strikes and lock outs. The Rashtrapati came out with this appeal some time ago in the name of self-reliance The Prime Minister has supported the Rashtrapati's plea on one or two occasions and this morning I find that speaking in his capacity as chairman of the National Productivity Council, somewhere in Delhi, today, the Minister of Industrial Development, Shri Momul Haque Choudhury has also appealed to the working class and trade unions to agree to a moratorium on strikes

SHRI S M BANERJEE (Kanpur) And pay income-tax

SHRI INDRAJIT GUPTA I think that this is a very appropriate moment when this whole issue of the labour relations policy of this Government should be debated and discussed in Parliament

The key importance, in the whole structure of industrial planning and economic planning, of labour relations policy has been totally overlooked in this country I think the hon Minister should pay a little attention to this matter But I would request him that on the next occasion when Government in their official capacity would reply to this resolution, the hon Minister in charge, Shri Khadilker should be present because I want to know exactly, when he replies, what Government propose to do No assurances will satisfy me I want to know whether Government are going to adopt a new policy or not

16 56 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARI *in the Chair*]